



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आषाढ़ 1939 (श10)
(सं० पटना 541) पटना, बुधवार, 28 जून 2017

सं० 08/आरोप-01-307/2014-7435-सां०प्र०
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प
16 जून 2017

श्री सुधांशु कुमार चौबे, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1089/08, 858/11 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गायघाट, मुजफ्फरपुर के विरुद्ध योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता एवं सरकारी राशि के दुर्विनियोग के आरोपों पर निगरानी थाना कांड सं०-98/2008, दिनांक 25.11.2008 दर्ज हुआ। जिसमें ये प्राथमिकी अभियुक्त बनाये गये। एतद्संबंधी निगरानी विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त अनुशंसा (पत्रांक-17 नि०गो०, दिनांक 23.01.2009) के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-434, दिनांक 09.02.2009 द्वारा श्री चौबे को निलंबित किया गया। जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक-1085, दिनांक 13.04.2009 द्वारा श्री चौबे के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के निमित्त आरोप, प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया। श्री चौबे ने अपने निलंबनादेश के विरुद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। संदर्भित सी० डब्ल्यू० जे० सी० सं०- 13805/09 में दिनांक 04.11.2009 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभागीय संकल्प ज्ञापांक-535, दिनांक 18.01.2010 द्वारा आदेश निर्गत होने की तिथि से श्री चौबे को निलंबन मुक्त कर दिया गया।

2. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से प्राप्त आरोप, प्रपत्र 'क' की प्रति संलग्न करते हुए श्री चौबे से स्पष्टीकरण माँगी गयी। इस क्रम में उन्होंने अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया जिसपर संबंधित जिला पदाधिकारी से मंतव्य की माँग की गयी। जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर ने अपने पत्रांक-1199, दिनांक 12.04.2013 द्वारा यथा वांछित मंतव्य उपलब्ध कराया तथा श्री चौबे के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं बताया। उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत आरोपों की वृहद जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-8936, दिनांक 07.06.2013 द्वारा श्री चौबे के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

3. संचालन पदाधिकारी यथा संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच) पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-2309, दिनांक 19.11.2014 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें श्री चौबे के विरुद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित बताया गया। अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया। तदुपरांत आरोपवार अनुशासनिक प्राधिकार के असहमति में निहित आरोपों की प्रमाणिकता को स्पष्ट करते हुए विभागीय पत्रांक-9199, दिनांक 25.06.2015 द्वारा श्री चौबे से लिखित अभिकथन माँगा गया। इस क्रम में श्री चौबे का स्पष्टीकरण (पत्रांक-978, दिनांक 08.07.2015) प्राप्त हुआ।

4. आरोप प्रपत्र 'क', संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं श्री चौबे से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षापरांत आरोपों को प्रमाणित पाते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 14530 दिनांक 25.10.2014 द्वारा श्री चौबे को निम्न दंड संसूचित किया गया :-

- (i) निन्दन (आरोप वर्ष-2005-06 के प्रभाव से)।
- (ii) दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।
- (iii) निलंबन अवधि (दिनांक 09.02.09 से दिनांक 18.01.2010) के संबंध में निर्णय हेतु अलग से कार्रवाई करते हुए आदेश निर्गत किया जायेगा।

5. तदोपरांत विभागीय पत्रांक 14671 दिनांक 27.10.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-11(5) के तहत श्री चौबे से निलम्बन अवधि 09.02.2009 से 18.02.2010 तक के वेतनादि भुगतान के संबंध में कारण पृच्छा किया गया। पत्रांक-1/कैम्प दिनांक 16.11.2016 द्वारा श्री चौबे ने अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया। पुनः श्री चौबे द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 14530 दिनांक 25.10.2016 द्वारा अधिरोपित शास्ति पर पुनर्विचार करने हेतु अभ्यावेदन (पत्रांक-Camp 01 दिनांक 09.12.2016) भी दिया गया।

6. पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में श्री चौबे ने कहा है कि विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने आरोपों को अप्रमाणित बताया था। साथ ही निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने अनुसंधान में उन्हें निर्दोष बताते हुए अन्य अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है। असहमति के बिन्दु पर उनका कहना है कि एक ही तिथि को उन्होंने दो बार अग्रिम नहीं दिया था और अभिलेख संसारण में कोई त्रुटि नहीं की गयी थी। अभिलेखों की स्वच्छ प्रति के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि एक ही तिथि में दो बार अग्रिम नहीं दिये जाने संबंधी श्री चौबे का दावा सही है परन्तु अभिलेखों के संधारण में बैंक डेटिंग संबंधी घोर त्रुटि है। श्री चौबे द्वारा ही समर्पित अभिलेख में एक आदेशफलक पर दिनांक 30.06.2007 की तिथि में हस्ताक्षर हैं। पुनः उसके बाद एक वर्ष पिछे की तिथि में दिनांक 30.06.2006 को उन्होंने ही स्वयं आदेशफलक पर अपना आदेश अंकित किया है। कार्य के बदले अनाज योजना मूलतः मजदूरी भुगतान के लिए होता है जिसमें सप्ताहिक मजदूरी का भुगतान किया जाता है। मात्र रु 7500/- के अग्रिम के बाद रु 125000/- (एक लाख पच्चीस हजार) और उसके बाद बिना समुचित अग्रिम के रु 304844/- (तीन लाख चार हजार आठ सौ चौवालीस) का नापी आ जाना घोर प्रक्रियात्मक उल्लंघन है जिस पर श्री चौबे ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है।

पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने अपने पत्रांक 1050 दिनांक 05.06.2012 द्वारा सूचित किया कि अनुसंधान के उपरांत प्राथमिकी अभ्युक्त श्री सुधाशु कुमार चौबे, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गयाघाट, श्री रामदेव चौधरी, कार्यपालक अभियंता विशेष प्रमंडल, मुजफ्फरपुर एवं श्री माया नन्द मिश्र, सहायक अभियंता, प्रखंड गायघाट, मुजफ्फरपुर को अनुप्रेषित दिखाते हुए अन्य अभियुक्तों श्री रफूल इसलाम, तत्कालीन कनीय अभियंता एवं श्री नरेन्द्र झा, पंचायत सचिव के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या 50/12 दिनांक 28.05.2012 माननीय न्यायालय में समर्पित किया गया। श्री चौबे द्वारा इसे पुनर्विलोकन आवेदन में आधार मानकर तर्क दिया जा रहा है कि वे निर्दोष सिद्ध हुए हैं परन्तु नापी पुस्त में गड़बड़ी एवं मस्टर रोल के संधारण में अनियमितता के लिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने पंचायत सचिव एवं कनीय अभियंता को दोषी माना है एवं उनके विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। वर्णित स्थिति में प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता एवं सहायक अभियंता अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण में चूक के लिए दोषी कैसे नहीं होंगे। अभिलेख संधारण में त्रुटि, मस्टर रोल में अनियमितता, पर्यवेक्षण में चूक एवं अनुश्रवण की कमी के बिन्दु पर श्री चौबे का तर्क स्वीकारण योग्य नहीं है।

7. निलंबन अवधि दिनांक 09.02.2009 से दिनांक 18.01.2010 की विनियमन पर श्री चौबे ने तर्क दिया है कि वे विभागीय कार्यवाही में निर्दोष सिद्ध हुए थे एवं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने अनुसंधान में उनके विरुद्ध आरोप प्रमाणित नहीं पाया था। अतः निलंबन अवधि के लिए उन्हें पूर्ण वेतन दिया जाय। श्री चौबे का तर्क बिन्दुवार वही है जो पुनर्विलोकन आवेदन में दिया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। एक ही तिथि को उन्होंने दो बार अग्रिम नहीं दिया है परन्तु मजदूरों को सप्ताहिक रूप से मजदूरी का भुगतान हो यह सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम देने की प्रक्रिया में सुधार नहीं किया गया है। जून 2007 में आदेशफलक पर आदेश दिये जाने के बाद फिर पीछे की तिथि में भी आदेश निर्गत किया गया। इससे सिद्ध होता है कि अभिलेख संधारण में त्रुटि बरती गयी है।

अतः श्री सुधाशु कुमार चौबे, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक-1089/08, 858/11 तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, गायघाट, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सचिव, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना के तर्कों को अस्वीकृत करते हुए निम्न निर्णय लिया जाता है:-

- (क) पुनर्विलोकन आवेदन को अस्वीकृत करते हुए दी गयी निम्नलिखित शास्ति (i) निन्दन (आरोप वर्ष 2005-06 के प्रभाव से) (ii) 2 (दो) वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक, को यथावत रखा जाता है।

(ख) निलंबन अवधि दिनांक 09.02.2009 से दिनांक 18.01.2010 के लिए मात्र 75 प्रतिशत ही वेतन देय होगा, परन्तु अन्य प्रयोजनों के लिए यह सेवा अवधि मानी जाएगी।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 541+571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>